



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रपतासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, असमार, १० नवम्बर, १९९४/२८ कालिक, १९१६

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं प्राम योजना विभाग

अधिसूचनाएँ

शिमला-१७१००२, १४ नवम्बर, १९९४

संख्या पी० बी० डब्ल्य० (बी) १५-१४/८३-१.—हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि, शहरी और नगरीय अधीन व्यवस्थापनों (सटलमैट्स) वे विकास के लिय बहुकेन्द्रीय योजना (स्टैटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं प्राम योजना अधिनियम, १९७७ के अधीन सूचित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत करके शहरी विकास और नगरीय व्यवस्थापनों के विकास के लिए भी एवं इन विकास प्राधिकरण का स्थापन करना चाहिए।

भत: राज्य सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्या पी० डब्ल्य० (बी)-१५ (१४)८३/, तारीख १४-१२-१९८३ द्वारा, हिमाचल प्रदेश नगर एवं प्राम योजना अधिनियम, १९७७ की धारा ४० और ४२(क) के अधीन; स्यापित/गठित शिमला विकास प्राधिकरण का बना रहना अनावश्यक है।

भ्रत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नगर एवं प्राम योजना अधिनियम, १९७७ की धारा-७८(१) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त प्राधिकरण को तुरन्त प्रभाव से विचटित करते हैं।

शिमला-171002, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी० बी० डब्ल्य० (बी)-15-14/83-I-हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि, शहरी और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सेटलमेंट्स) के विकास के लिये बहुकन्द्रीय योजना (स्ट्रेटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन सुजित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत करके शहरी विकास और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सेटलमेंट्स) के विकास के लिए भी एकीकृत विकास प्राधिकरण का स्थापन करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि, इस अधिसंचयन के साथ संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट योजना क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 40 (1) के अधीन स्थापित/ पदाविहित हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का नगर एवं विकास प्राधिकरण के रूप में बना रहना अनावश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 78(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त प्राधिकरणों (इन अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित) को तुरन्त प्रभाव से विघटित करते हैं।

अधिसूचना संख्या: पी० बी० डब्ल्य० (बी) 15-14/83-I दिनांक 14-11-1994 का परिशङ्खा

योजना क्षेत्र का नाम

अधिसूचना संख्या व तिथि जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण के रूप में नमोर्दिष्ट (डिजीगेट) फिया गया था

1

2

1. मण्डो योजना क्षेत्र

संख्या: पी० बी० डब्ल्य० (बी० एण्ड आर०) (बी) 4( 10) 4/84, दिनांक 29-7-1985.

2. हमीरपुर योजना क्षेत्र

संख्या: पी० बी० डब्ल्य० (बी० एण्ड आर०) 28 (15)/85, दिनांक 13-03-1986.

3. धर्मगढ़ा योजना क्षेत्र

संख्या: पी० बी० डब्ल्य० (बी० एण्ड आर०) (बी) 4 (11)-5/84, दिनांक 21-05-1986.

4. परवाणू योजना क्षेत्र

संख्या: पी० बी० डब्ल्य० (बी० एण्ड आर०) (बी), 15 (1) 3/81, दिनांक 14-8-1986.

5. बरोटीवाला योजना क्षेत्र

संख्या: पी० बी० डब्ल्य० (बी० एण्ड आर०) (बी) 15 (1) 3/81, दिनांक 14-8-1986.

शिमला-171002, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी०बी०डब्ल्य० (बी०) 15-14/83-I.—हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि, शहरी और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सेटलमेंट्स) के विकास के लिये बहुकन्द्रीय योजना (स्ट्रेटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन सुजित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत करके शहरी विकास और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सेटलमेंट्स) के विकास के लिए भी एकीकृत विकास प्राधिकरण का स्थापन करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश भरकार की यह राय है कि, अधिसूचना मंड़ा पी० निर्णय (ब) 28-26/85 तारीख 25-11-1991 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 66 और 67 के अधीन कुल्लू घाटा विशेष क्षेत्र के लिये स्थापित और गठित विषय क्षेत्र विकास प्राधिकरण को वना रहना अनिवार्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 78 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त प्राधिकरण को तुरन्त प्रभाव में विद्युतित करते हैं।

गिमल:-171002, 14 नवम्बर, 1994

मंड़ा पी० बी० डब्ल्य० (बी) 15-14/83-I.—हिमाचल प्रदेश भरकार की यह राय है कि, शहरी और चौपिन ग्रामीण व्यवस्थायों (मैटलमैट) के विकास के लिये बहुकेन्द्रीय योजना (स्ट्रैटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन सूचित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत तरके शहरी विकास और चौपिन ग्रामीण व्यवस्थायों (मैटलमैट) के विकास के लिए भी एकीकृत विकास प्राधिकरण का स्थापना कराया जाइए।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना में संशय अनुसूची में विनियोग योजना क्षेत्रों/विशेष क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के नाम ने जान प्राधिकरण की स्थापना करते हैं।

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण का मुख्यालय गिमला में होगा।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अदेश देते हैं कि अधिसूचना मंड़ा पी० बी० डब्ल्य० (बी) 15-14/83-I तारीख 14-11-1994 द्वारा विवरित लिए गए शिक्षण, विकास प्राधिकरण, कुल्लू घाटी विशेष क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, हमीरपुर, धर्मगढ़, मण्डी, परवाणु और वरोटीवाला योजना क्षेत्रों के लिये नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण की सभी आस्तियाँ और उत्तरदायित्व हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण में तुरन्त प्रभाव ने अंतिम होंगे।

अधिनियम संघरा पी० बी० डब्ल्य० (बी) 15-14/83-I, दिनांक 14-11-1994 का परिशिष्ट

योजना क्षेत्र का नाम :

1. वरोटीवाला
2. चम्पा
3. धर्मगढ़
4. डलहीजी
5. हमीरपुर
6. महतपुर
7. मण्डी
8. नालागढ़
9. पालमपुर
10. नाहन
11. पांचाला साहित्य
12. परवाणु

13. रामपुर वुणहर
14. रोहड़
15. सराहन (सिरमीर)
16. शिमला
17. ठियोग
18. ऊन।
19. कसीली

विशेष योजना क्षेत्र का नाम :

1. कुल्ल धाटी विशेष क्षेत्र
2. हटकोटी विशेष क्षेत्र
3. पट्टोह मील
4. चमरा जलाशय
5. पौंग खेत

शिमला-171002, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (बी) 15-14/83-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण का निम्नलिखित रूप से तुरन्त प्रभाव से गठन करने का आदेश देते हैं :—

1. मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश	अधिकारी
2. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार	मंत्री
3. मंत्रिव (टी० सी० पी०) हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
4. सचिव (वित), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
5. मुख्य प्रशासक, हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण	सदस्य
6. मेयर, नगर निगम, शिमला	सदस्य

आदेश द्वारा

पी० एस० नेही,  
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of this Department notification No. PBW(B) 15-14/83-I, dated 14.11.1994 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### NOTIFICATIONS

Shimla-171002, the 14th November, 1994

No. PBW (B)15-14/83-I.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh is of the opinion that a unified development authority for urban development and also for the development of selected rural settlements should be established by integrating the existing authorities

created under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 to achieve multi-centred strategy to develop urban and selected rural settlement.

Whereas the State Government is of the opinion that it is un-necessary to continue with the Shimla Development Authority established/constituted under section 40 and 42(A) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 *vide* Notification No.PW (B) -15(14)/23, dated 14-12-1983.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under section 78 (i) of the Town and Country Planning Act, 1977 is pleased to dissolve the aforesaid authority with immediate effect.

[Authoritative English text of this Government notification No. PBW(B) 15-14/83-I, dated 14-11-1994 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

Shimla-2, the 14th November, 1994

No. PBW(B)15-14/83-I.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh is of the opinion that a unified development authority for urban development and also for the development of selected rural settlements should be established by integrating the existing authorities created under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, to achieve multi-centred strategy to develop urban and selected rural settlements.

Whereas State Government of Himachal Pradesh is of the opinion that it is un-necessary to continue with Himachal Pradesh Housing Board as Town and Country Development Authority established/designated under section 40(i) of the Town and Country Planning Act, 1977, for the planning areas as specified in the schedule attached with this notification.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him u/s 78 (i) of the Town and Country Planning Act, 1977, is pleased to dissolve the aforesaid authorities (mentioned in the schedule attached with this notification) with immediate effect.

Schedule attached to the Notification No. PBW (B) 15-14/83-I, dated 14-11-1994.

Name of Planning Area	No. and date of notification <i>vide</i> which Himachal Pradesh Housing Board was designated as Town and Country Development Authority
1. Mandi Planning Area	No. PBW (B&R) (B) 4(10)4/84, dated 29-7-1985.
2. Hamirpur Planning Area	No. PBW (B&R) 28(15)/85, dated 13-03-1986.
3. Dharamshala Planning Area	No. PBW (B&R) (B) 4(11)-5/84, dated 21-05-1986.
4. Parwanoo Planning Area	No. PBW(B&R) (B) 15(1)3/81, dated 14-08-1986
5. Barotiwala Planning Area	-do-

[Authoritative English text of this Department notification No. PBW (B) 15-14/83-I, dated 14-11-1994, required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Shimla-2, the 14th November, 1994

No. PBW(B)15-14/83-I.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh is of the opinion that a unified development authority for urban development and also for the development

of selected rural settlements should be established by integrating the existing authorities created under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, to achieve multi-centred strategy to develop urban and selected rural settlements;

Whereas the State Government is of the opinion that it is un-necessary to continue with the Special Area Development Authority for the Kullu Valley Special Area established/constituted under sections 66 and 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 *vide* notification No. Lok Nirman (kha) 28-26/85, dated 25-11-1991.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him ~~under section 76(4)~~ of the Town and Country Planning Act, 1977 is pleased to dissolve the aforesaid authority with immediate effect.

-----

[Authoritative English text of this Government notification No. PBW(B) 15-14/83-I, dated 14-11-1994 required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

Shimla-I, the 14th November, 1994

No. PBW (B) 15-14/83-I.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh is of the opinion that a unified development authority for urban development and also for the development of selected rural settlements should be established by integrating the existing authorities created under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 to achieve multi-centred strategy to develop urban and selected rural settlements.

Now therefore, in exercise of the powers conferred upon him under section 40 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to establish an authority to be known as the Himachal Pradesh Nagar Vikas Pradhikaran with immediate effect for the planning areas/special areas as specified in the schedule annexed to this Notification.

The headquarter of the Himachal Pradesh Nagar Vikas Pradhikaran shall be at Shimla.

And further, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that all the assets and liabilities of the Shimla Development Authority, Special Area Development Authority for Kullu Valley Special Area, the Town and Country Development Authority for planing areas viz. Hamirpur, Dharamshala, Mandi, Parwanoo and Barotiwala dissolved *vide* Notifications No. PBW (B)15-14/83-I dated 14-11-1994 shall stand transferred to the Himachal Pradesh Nagar Vikas Pradhikaran with immediate effect.

#### SCHEDULE

ANNEXURE TO NOTIFICATION NO. PBW(B)15-14/83-I, DATED 14-11-1994.

Name of the Planning Area:

1. Barotiwala.
2. Chamba.
3. Dalhousie.
4. Dharamshala.
5. Hamirpur.
6. Mehaptur.
7. Mandi.

8. Nalagarh.
9. Palampur.
10. Nahan.
11. Poanta Sahib.
12. Parwanoo.
13. Campbell Bushahar.
14. Rohroo.
15. Sarahan (Sirmaur).
16. Shimla.
17. Theog.
18. Una.
19. Kasauli.

**Name of Special Planning Areas:**

1. Kullu Valley Special Area.
2. Hatkoti Special Area.
3. Pandoh Lake.
4. Chamera Reservoir.
5. Pong Dam.

[Authoritative English text of this Department Notification No. PBW(B)15-14/83-I, dated 14-11-1994 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Shimla-I, the 14th November, 1994

No. PBW(B)15-14/83-I.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him u/s 42 of the Town and Country Planning Act, 1977 is pleased to constitute the Himachal Pradesh Nagar Vikas Pradhikaran with immediate effect as follows:—

1. Chief Minister of Himachal Pradesh	.. Chairman
2. Chief Secretary to Government of Himachal Pradesh	.. Member
3. Secretary (TCP) to Government of Himachal Pradesh	.. Member
4. Secretary (Finance) to Government of Himachal Pradesh	.. Member
5. Chief Administrator of Himachal Pradesh Nagar Vikas Pradhikaran	.. Member
6. Mayor of Municipal Corporation, Shimla.	.. Member

By order,

P. S. NEGI,  
Financial Commissioner-cum-Secretary.